गुरपाल सिंह

बनाम

राजस्थान उच्च न्यायालय

(2006 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 200)

27 नवंबर, 2012।

[सुरिंदर सिंह निजार और एच. एल. गोखले, जे. जे.]

राजस्थान सेवा नियम, 1951:

नियम 54 - निलंबन की अवधि के लिए वेतन और दोषमुक्ति अधिकारी को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ा-मुकदमे और अपील लंबित रहने तक निलंबन के तहत रखा गया-बरी-दाण्डिक अपीलीय खारिज होने के बाद विभागीय कार्यवाही के दौरान निलंबन जारी रहा-आयोजितःनिचली अदालत द्वारा दोषमुक्ति जाने पर और उच्च निचली अदालत के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के विचाराधीनता को पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है-हालांकि, निचली अदालत और उच्च निचली अदालत के निष्कर्षों को देखते हुए, दाण्डिक अपीलीय में निर्णय के बाद याचिकाकर्ता का निरंतर विचाराधीनता पूरी तरह से अनुचित था-याचिकाकर्ता दाण्डिक अपीलीय में निर्णय की तारीख से पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार था-विभागीय कार्यवाही में आरोप साबित नहीं हुए हैं और याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है और विचाराधीनता की अवधि को ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में माना गया है, वह उस तारीख से पदोन्नति के लिए विचार करने का हकदार है जब उसके कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत किया गया था और तदनुसार सभी परिणामी लाभों की अनुमति दी गई थी, दाण्डिक अपीलीय के निर्णय की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ-सेवा कानून-न्यायिक याचिकाकर्ता, राजस्थान में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, को

24.11.1985 पर मृत पाए गए एक अधिवक्ता की पत्नी द्वारा दिनांकित 11.12.1985 की शिकायत के अनुसार 20.12.1985 पर गिरफ्तार किया गया था।उसने आरोप लगाया कि उसका पति याचिकाकर्ता से वह पैसा वापस करने के लिए कह रहा था जो उसने याचिकाकर्ता को पाने के लिए लिया था।

राजस्व बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त दिनांक 22.12.1985 के एक आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता 20.12.1985 से निलंबित कर दिया गया था। आपराधिक मुकदमा, जिसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, याचिकाकर्ता को 1.5.2002 पर दोषमुक्ति दिया गया। सी. बी. आई. द्वारा दायर अपील को भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27.9.2005 पर खारिज कर दिया था। मुकदमे और अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के अधीन रहा

लगभग 20 वर्षों के लिए निलंबन जब याचिकाकर्ता को पता चला कि निलंबन आदेश को रद्द करने के बजाय, उच्च न्यायालय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा था

उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए, उन्होंने निलंबन के आदेश को रद्द करने और परिणामी लाभों के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की। 27.2.2008, दिनांकित जाँच रिपोर्ट में, याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी कर दिया गया था, और दिनांक 26.3.2008 के आदेश द्वारा, उसे बहाल कर दिया गया था और 12.5.2008 पर पोस्टिंग दी गई थी। वे सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

24.1.2009 पर, उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि याचिकाकर्ता के निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर माना जाएगा लेकिन बिना वेतन के। उसे पहले से दिए गए निर्वाह भत्तों को छोड़कर और वह किसी भी पदोन्नति का हकदार नहीं होगा। पारित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर परिणाम राजस्थान

सेवा नियम, 1951 के नियम 54 के तहत उचित आदेश देते हुए, उच्च न्यायालय ने 16.5.2011 दिनांकित आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि जिस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के निलंबन को उप-आर के तहत पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है।(2) आर.54 और अपने पहले के आदेश दिनांक 24.1.2009 को दोहराया।

आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1.बहाली पर वेतन और अन्य भत्तों के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता से संबंधित मुद्दे को निर्धारित आदेशने के लिए, मामले की विभिन्न चरणों/समय पर जांच आदेशने की आवश्यकता है।पहला चरण उस समय शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता को शुरू में 22.12.1985 W. E. F. 20.12.1985 पर निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता प्रारंभिक चरण में अपने निलंबन के खिलाफ वैध रूप से विरोध नहीं कर सकता है, जब वह अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रहा था, हालांकि दुर्भाग्य से उन परिस्थितियों के लिए जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं था ।यह निलंबन स्वाभाविक रूप से तब भी जारी रहा जब वह हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे थे। अगला चरण वह है जब उसे निचली निचली अदालत ने 1.5.2002 पर बरी कर दिया था हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि जैसे ही निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया था, राजस्थान उच्च निचली अदालत को इसके निलंबन आदेश को तुरंत रद्द करने की आवश्यकता थी। निस्संदेह, याचिकाकर्ता को एक गैर-संवेदनशील नियुक्ति दी जा सकती थी, जिसमें न्यायिक कार्य शामिल नहीं थे। लेकिन, उच्च न्यायालय के लिए उस स्तर पर निलंबन को रद्द करना अनिवार्य नहीं था। यह एक बात है कि अभिलेख, कि अभियोजन अभिकरण ने दाखिल करने का निर्णय लिया और वास्तव में, एक अपील दायर की जो 27 पर निर्णय होने तक लंबित रही।इसलिए, निचली निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अंतिम नहीं थे।वे उच्च न्यायालय द्वारा अपील में

उलट दिए जाने के लिए उत्तरदायी थे।इस प्रकार, उक्त अवधि/चरण के दौरान, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के निलंबन की निरंतरता थी पूरी तरह से अनुचित। जब तक दाण्डिक अपीलीय में याचिकाकर्ता के दोषमुक्ति के फैसले को दोहराया नहीं गया, तब तक राजस्थान उच्च न्यायालय को एक बहुत ही तीखी स्थिति में रखा गया था। उच्च न्यायालय के पास याचिकाकर्ता को निलंबित करने और रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, याचिकाकर्ता, जो एक न्यायिक अधिकारी के रूप में समाज में बहुत उच्च पद पर था, हत्या के अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था, जो उच्चतम नैतिक अधमता का अपराध था। [पैरा 32-35] [158-C-F; 153-E-H; 154-A-B-D-E]

दया शंकर बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य। पंजीयक & Ors.1987 (3) एस. सी. सी. 1; और रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायाधीश पूर्वाह्न भट्टाचार्जी और अन्य द्वारा से, 1995 (3) पूरक।एस. सी. आर. 319 = 1995 (5) एस. सी. सी. 457-संदर्भित

1.2.जहां तक दाण्डिक अपीलीय खारिज होने के बाद के चरण का संबंध है, याचिकाकर्ता के दोषमुक्ति की पुष्टि होने के बाद, राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए निर्णय लेना आवश्यक था।आयनः(क) क्या निलंबन के आदेश को निरस्त किया जाए और याचिकाकर्ता को न्यायिक कार्य करने की अनुमति दी जाए; (ख) मृतक से उसके द्वारा धन की कथित प्राप्ति के संबंध में विभागीय जांच की जाए या नहीं; (ग) निलंबन की अवधि को कैसे माना जाए; (घ) क्या याचिकाकर्ता निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन, आंशिक वेतन या कोई वेतन पाने का हकदार था या नहीं। [पैरा 39] [157-सी-ई]

1.3.यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि निचली निचली अदालत का फैसला स्पष्ट रूप

से इंगित करता है कि प्रस्तुत साक्ष्य आवश्यक न्यूनतम मानक तक भी नहीं पहुंचता है याचिकाकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए।इसने अभियोजन पक्ष के मामले की नींव पर ही विश्वास नहीं किया।कथित मकसद बिना किसी आधार के पाया गया है। निचली निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मामले की विषम परिस्थितियों में, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक थी।निचली निचली अदालत को एक निश्चित धारणा के साथ छोड़ दिया गया था कि साक्ष्य के साथ "छेड़छाड़" की गई थी।इसने स्पष्ट रूप से देखा कि "जांच ने कुछ तत्वों के प्रभाव में पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह का प्रदर्शन किया, जो शत्रुतापूर्ण थे।

ये अवलोकन तत्काल मामले को उन मामलों के दायरे में लाएंगे जिन्हें अक्सर "कोई सबूत नहीं" के मामलों के रूप में वर्णित किया जाता है।इसके अलावा, उच्च अदालत ने अपील को आत्यन्तिक रूप से कोई योग्यता नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा, पहला, कि कोई हत्या हुई थी और दूसरा, कि आरोपी वही था जिसने इसे किया था।[पैरा 33 और 38] [152-एफ-जी; 153-ए-डी; 157-सी]

1.4.निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, और दाण्डिक अपीलीय में उच्च निचली अदालत द्वारा दोहराया गया, याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत जारी रखने का निर्णय, इसके बाद, यह काफी कठोर था। यह सच है कि याचिकाकर्ता का निलंबन जारी रखा गया था क्योंकि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ इस आरोप पर विभागीय जांच करने का फैसला किया था कि उसने मृतक से गलत तरीके से कुछ पैसे निकाले थे। लेकिन यह रिकॉर्ड की बात है कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत दोनों ने पैसे की कथित प्राप्ति के संबंध में पूरी कहानी को गलत पाया था। जाँच उन्हीं तथ्यों और उन्हीं साक्ष्यों पर आधारित थी

जिनकी जाँच निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत द्वारा भी की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च निचली अदालत के लिए यह आवश्यक था कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेने से पहले निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत के निष्कर्षों की विस्तार से जांच करे, जो तथ्यों और साक्ष्यों के एक ही समूह पर आधारित हो। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा फैसले की ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी। नागपुर नगर निगम के मामले में, यह देखा गया है कि उन्हीं आरोपों या आधारों या साक्ष्य पर विभागीय जांच जारी रखना समीचीन नहीं हो सकता है, जहां आरोपी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया है और आरोपों से पूरी तरह से बरी कर दिया गया है।[पैरा 27 और 40] [149-बी; 157-ई-एच; 158-ए-बी]

नागपुर शहर निगम, सिविल लाइन्स, नागपुर और अन्र। बनाम रामचंद्र और अन्य। 1981 (3) एससीआर 22 = 1981 (2) एससीसी 714; पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली बनाम नरेंद्र सिंह, 2006 (3) एससीआर 872 = 2006 (4) धारा 265; और जसबिर सिंह अन्य पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य। 2006 (8) पूरक।एससीआर 62 = 2007 (1) एससीसी 566-संदर्भित।

1.5.याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेने के बाद भी, याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत जारी रखना अनिवार्य नहीं था।याचिकाकर्ता पर अब किसी भी आपराधिक अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था क्योंकि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत दोनों ने निष्कर्ष निकाला था कि उनके खिलाफ आरोप याचिकाकर्ता को मनगढ़ंत बनाया गया था।याचिकाकर्ता को 22.12.1985 के बाद से निरंतर निलंबन के अधीन किया गया था।विभागीय कार्यवाही की अवधि के दौरान, भले ही याचिकाकर्ता को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाना था, उच्च

न्यायालय आसानी से उसे प्रशासनिक पक्ष में उपयुक्त नियुक्ति दे सकता था। ओ. पी. गुप्ता में इस मामले में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय तक निरंतर निलंबन सरकारी कर्मचारी को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है।चूंकि निलंबन का आदेश सरकार को अधिकार देता है कर्मचारी को केवल "निर्वाह भत्ता" दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि "जीवन" अभिव्यक्ति केवल जानवरों के अस्तित्व या जीवन द्वारा से निरंतर कठिन परिश्रम को नहीं दर्शाती है।[पैरा 30 और 40] [150-ई-जी; 158-बी-डी]

ओ पी गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य। 1988 (1) एस. सी. आर. 27 = 1987 (4) धारा 328-पर निर्भर

1.6.एक बार फिर यह रिकॉर्ड की बात है कि विभागीय जांच में भी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए और उसे बरी कर दिया गया।इसके बाद याचिकाकर्ता के निलंबन को 26.3.2008 पर रद्द कर दिया गया था, लेकिन बिना कोई निर्देश दिए कि निलंबन की अवधि को कैसे माना जाना था।यह केवल बाद में था कि नियमितीकरण के संबंध में मामला आयोजित बैठक में पूर्ण न्यायालय द्वारा उनके निलंबन की अवधि पर विचार किया गया और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा, लेकिन पहले से ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते को छोड़कर वेतन के बिना। उक्त संकल्प के आधार पर, उच्च न्यायालय ने 24.1.2009 दिनांकित आदेश पारित किया। इसलिए 24.1.2009 दिनांकित आदेश द्वारा भी, याचिकाकर्ता को केवल आंशिक राहत दी गई थी। [पैरा 41] [158-ई-एफ-एच; 159-ए]

1.7.घटनाओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की यह सुविचारित

राय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील खारिज किए जाने की तारीख से याचिकाकर्ता को वेतन देने से इनकार करना अन्यायपूर्ण होगा। नियम 54 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के लिए एक विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेश पारित करना आवश्यक था कि क्या निलंबन की अवधि पूरी तरह से अनुचित थी। निस्संदेह, नियम 54 के तहत शक्ति विवेकाधीन है लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग उचित रूप से और निर्णय के लिए प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता के आपराधिक आरोपों से दोषमुक्ति पर, विभागीय जांच विचाराधीनता रहने के दौरान उसे निलंबन में रखने की आवश्यकता नहीं थी।उच्च न्यायालय नियम 54 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का ठीक से प्रयोग करने में विफल रहा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 5.4.2011 आदेश में निर्देश दिया गया था।विभागीय पूछताछ विचाराधीनता रहने के दौरान भी उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने पर याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द कर दिया जाना चाहिए था।[पैरा 42] [159-सी-जी]

1.8.इन परिस्थितियों में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने के समय से, याचिकाकर्ता का निरंतर निलंबन पूरी तरह से अनुचित था।द.

इसलिए याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की तारीख से पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार है।[पैरा 40 और 46] [158-डी; 160-एच; 161-ए]

2.1.यह अभिलेख की बात है कि दोषमुक्त होने पर विभागीय जाँच में, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया।उसे कोई सजा नहीं दी गई। हालाँकि, आपराधिक मुकदमे विचाराधीनता रहने और विभागीय कार्यवाही के दौरान, जब उनके कनिष्ठ व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाता था, तो उन्हें पदोन्नति के लिए नहीं माना जाता था।उच्च न्यायालय ने पूर्ण न्यायालय, संकल्प दिनांक 29.11.2008 और

संचार दिनांक 24.1.2009 में निर्देश देने में गलती की कि याचिकाकर्ता किसी भी पदोन्नति का हकदार नहीं होगा। याचिकाकर्ता उस तारीख से वैचारिक रूप से पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार था जब उनके कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत किया गया था।इसलिए, उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता के मामले पर पदोन्नति के लिए विचार करने का निर्देश दिया जाता है (यदि वह अन्यथा संतुष्ट करता है) नियमों के अनुसार आवश्यकताएँ) उस तारीख से जब उससे कनिष्ठ व्यक्ति पर विचार किया गया और उसे अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया।याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा, जैसे कि वेतन और अन्य भत्ते, उसे उस तारीख से प्रभावी रूप से कर्तव्य पर मानते हुए जब दोषमुक्ति के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय और उनका अंतिम वेतन तय करने के बाद सही ढंग से निकाला गया।उच्च न्यायालय द्वारा 27.9.2005 पर अपील खारिज होने की तारीख से उसे 6 प्रतिशत ब्याज के साथ परिणामी लाभों का भुगतान किया जाएगा।[पैरा 45-46] [160-D-F;

161-ए-डी]

भारत संघ और अन्य। अन्य के. वी. जानकीरमन और अन्य। 1991, (3) एस. सी. आर. 790 = 1991 (4) सेक 109-पर निर्भर

श्री मन्नी लाल बनाम श्री परमई लाल और अन्य। 1971 (1) एस. सी. आर. 798 = 1970 (2) एस. सी. सी. 462, मुहम्मद अयूब खुहरो बनाम सम्राट ए. आई. आर. (33) 1946 एस. आई. एन. ओ. 121, रॉबर्ट स्टुअर्ट वाउचोप बनाम सम्राट (1933) 61 आई. एल. आर. 168, विद्या चरण शुक्ला बनाम पुरुषोत्तम लाल कौशिक 1981 (2) एस. सी. आर. 637 = 1981 (2) एस. सी. सी. 84, आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ और अन्र। (1964) 5 एस. सी. आर. 431,; संभागीय अधीक्षक, उत्तर रेलवे

और ए. एन. आर. बनाम आर. बी. हनीफी (1976) लैब। एल.सी. 1403, गोविंद प्रसाद बनाम भारत का संघ एफ, (1980) आरएलडब्ल्यू 258;, भारत संघ और अन्य। बनाम संग्राम केशरी नायक 2007 (5) एससीआर 896 = 2007 (6) एससीसी 704; सुलेख चंद और सालेक चंद बनाम पुलिस आयुक्त & अन्य। 1994 (4) पूरक।एस. सी. आर. 119 = 1994 (3) पूरक।एस. सी. सी. 674, स्टेट ऑफ केरा/ए एंड ओआरएस। बनाम ई. के. भास्करन पिल्लई 2007 (5) एस. सी. आर. 251 = 2007 (6) धारा 524, भारत संघ और अन्य। बनाम लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह काद्यान और अन्र। 2000 (1) पूरक।एस. सी. आर. 722 = 2000 (6) एस. सी. सी. 698; भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन, नई दिल्ली बनाम भोपाल सिंह पांचाल 1993 (3) पूरक।एस. सी. आर. 586 = 1994 (1) एस. सी. सी. 541; कृष्णकांत रघुनाथ बिभवनेकर अन्य महाराष्ट्र राज्य और अन्य। 1997 (2) एससीआर 591 = 1997 (3) एससीसी 636; के. पोन्नम्मा (श्रीमती) अन्य केरा राज्य/ए और ओआरएस। 1997 (2) एससीआर 1149 = 1997 (9)

एस. सी. सी. 36; धनंजय बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालना 2003 (1) एस. सी. आर. 744 = 2003 (2) एस. सी. सी. 386, भारत संघ और अन्य। बनाम जयपाल सिंह 2003 (5) पूरक।

एस. सी. आर. 115 = 2004 (1) एस. सी. सी. 121, बलदेव सिंह अन्य भारत संघ और अन्य। 2005 ('जे) पूरक।एस. सी. आर. 961 = 2005 (8) एस. सी. सी. 747; एन. सेल्वराज बनाम कुंभकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड और अन्र। 2006 (9) एस. सी. सी. 172, बंशी धार बनाम राजस्थान राज्य और अन्र। 2006 (8) पूरक। एस. सी. आर. 78 = 2007 (1) एस. सी. £324, संभागीय नियंत्रण/ई. आर., गुजरात एस. आर. टी. सी. बनाम कादरभाई जे. सुथार 2007 (2) एस. सी. आर. 550 = 2007 (10) एस. सी. सी. 561, भारत संघ बनाम बी. एम. झा। 2001 (11) एस. सी.

आर. 661 = 2001 (11) सेक 632-उद्धृत

मामला कानून संदर्भः

1971 (1) एस. सी. आर. 798 उद्धृत पैरा 20

ए. आई. आर. (33) 1946 एस. आई. एन. ओ. 121 उद्धृत पैरा 20

(1933) 61 आई. एल. आर. 168 उद्धृत पैरा 20

(1976) लैब. एल.ग. 1403 उद्धृत पैरा 20

(1980) आर. एल. डब्ल्यू. 258 उद्धृत पैरा 20

1981 (2) एस. सी. आर. 637 उद्धृत पैरा 20

1988 (1) एस. सी. आर. 27 पैरा 20 पर निर्भर था।

(1964) 5 एस. सी. आर. 431 उद्धृत पैरा 20

2006 (3) पैरा 20 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 872

1981 (3) पैरा 20 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 22

2006 (8) पूरक।पैरा 20 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 62

1991 (3) एस. सी. आर. 790 पैरा 20 पर निर्भर था।

2007 (5) एस. सी. आर. 896 उद्धृत पैरा 20

1994 (4) पूरक।एस. सी. आर. 119 उद्धृत

2007 (5) एससीआर 251 उद्धृत

2000 (1) पूरक।एससीआर 722 उद्धृत किया गया

1993 (3) पूरक।एस. सी. आर 586 उद्धृत

1997 (2) एससीआर 591

1997 (2) एससीआर 1149

2003 (1) एससीआर 744

उद्धृत किया गया

उद्धृत किया गया

उद्धृत किया गया

2003 (5) पूरक।एस. सी. आर 115 उद्धृत

2005 (4) पूरक।एस. सी. आर 961 उद्धृत

2006 (8) पूरक।एस. सी. आर 78 उद्धृत

2007 (2) एससीआर 550

2007 (11) एससीआर 661

1987 (3) सेक 1

उद्धृत किया गया

उद्धृत किया गया

उद्धृत किया गया

1995 (3) पूरक।एस. सी. आर. 319 उद्धृत

पैरा 20

पैरा 20

पैरा 20

पैरा 24

पैरा 24

पैरा 24

पैरा 24

पैरा 24

पैरा 24

पैरा 24

पैरा 24

पैरा 24 ·

पैरा 36

पैरा 36

नागरिक मूल क्षेत्राधिकार 2006 रिट याचिका (सिविल) संख्या 200।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

एम. आर. काला, अमित कुमार सिंह, पी. ओ. शर्मा याचिकाकर्ता।

पल्लव शिशोदिया, अनीश मित्तल (सुनील कुमार जैन के लिए) उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय सुरिंदर सिंह निजार, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. इस याचिका में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, याचिकाकर्ता ने 20 दिसंबर, 1985 के निलंबन के आदेश को शून्य घोषित करके रद्द करने के लिए सरशियोरेराई की प्रकृति में एक रिट की मांग की है।याचिकाकर्ता एक घोषणा का भी दावा करता है कि 24 जनवरी, 2009 का आदेश अमान्य है और याचिकाकर्ता 20

दिसंबर, 1985 से 26 मार्च, 2008 तक निलंबन की अवधि के लिए सभी लाभों का हकदार है, जब उसे सेवा में बहाल किया गया था।

2.हम संक्षेप में प्रासंगिक तथ्यों का विज्ञापन कर सकते हैं जिनके आधार पर याचिकाकर्ता उपरोक्त राहत का दावा करता है।

3. 28 दिसंबर, 1979 को याचिकाकर्ता का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग (R.P.S.C) द्वारा सहायक लोक अभियोजक ग्रेड II के पद के लिए किया गया था। उन्होंने 28 जुलाई, 1980 तक उक्त पद पर कार्य किया। अगले ही दिन, यानी 29 जुलाई, 1980 को उन्हें राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए चुना गया और वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त हुए।कुछ समय के लिए वे बांसवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहे।इस अवधि के दौरान, उनके निर्णयों को औसत से ऊपर और ईमानदारी को "संदेह से परे" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।निरीक्षण रिपोर्ट में आगे यह टिप्पणी की गई थी कि "बार के सदस्यों, वादियों और अदालत में आने वाले व्यक्तियों के साथ उनके व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है।"ऐसा प्रतीत होता है कि उनके स्थानीय बार के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण उनका स्थानांतरण हुआ।

4. 24 नवंबर, 1985 को जयपुर शहर में रेलवे ट्रैक पर अजमेर पुलिया के पास लगभग दोपहर 1 बजे एक शव मिला था।शव की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेश चंद गुप्ता के रूप में की गई।24 नवंबर, 1985 को पुलिस स्टेशन जीआरपी, जयपुर में सीरियल नंबर 35/85 पर 'मराग' (मृत्यु) का मामला दर्ज किया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय बार एसोसिएशन, जिसका मृतक सदस्य था, ने विरोध किया कि जिस तरह से श्री सुरेश चंद गुप्ता को रेलवे ट्रैक पर मृत पाया गया था, उसकी उचित जांच नहीं की जा रही थी। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने जोर देकर कहा कि उनकी मृत्यु किसी

गड़बड़ी का परिणाम थी।11 दिसंबर, 1985 को, घटना के लगभग 20 दिन बाद, मृतक की पत्नी ने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता उसके पति की हत्या में शामिल था। अपनी लिखित शिकायत में, उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने घटना से लगभग तीन महीने पहले उसे सूचित किया था कि याचिकाकर्ता ने राजस्व बोर्ड के सदस्य के रूप में मृतक की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए 1 लाख रुपये की राशि की मांग की थी।उसने दावा किया कि याचिकाकर्ता को जो पैसा दिया गया था, उसकी व्यवस्था उसके मृत पति ने जमीन का एक भूखंड बेचकर की थी। उसने उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों से भी पैसे उधार लिए थे।उपरोक्त धन का भुगतान करने के बावजूद, उसके पति को कोई नियुक्ति नहीं दी गई थी।नतीजतन, उसका पति इस बात पर जोर दे रहा था कि याचिकाकर्ता उसे अनावश्यक रूप से भुगतान की गई राशि वापस कर दे। उसने दावा किया कि याचिकाकर्ता पैसे वापस करने के लिए सहमत हो गई थी और अपने पति को पूर्व निर्धारित स्थान पर मिलने के लिए कहा था।उनके पति 24 नवंबर, 1985 को शाम 5 बजे घर से निकले और वापस नहीं आए। इसलिए, उसने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने पैसे को लेकर विवाद के कारण उसके पति की हत्या कर दी होगी।

5. मृतक की पत्नी द्वारा की गई शिकायत के बारे में पता चलने पर, याचिकाकर्ता स्वयं 18 दिसंबर, 1985 को पुलिस स्टेशन गया और जाँच में शामिल होने की पेशकश की।उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द जांच पूरी करने का अनुरोध किया, क्योंकि इस बीच उनका तबादला कर दिया गया है और उन्हें वल्लभनगर में काम करना है।इस बीच, स्थानीय बार एसोसिएशन ने पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ आंदोलन जारी रखा।वकीलों ने हड़ताल का सहारा लिया और आने वाले कई दिनों तक अदालतों में काम ठप रहा।स्थिति इतनी गंभीर थी कि जब 20 दिसंबर, 1985 को

अग्रिम जमानत के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो बार एसोसिएशन के सदस्यों ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को मामले में बहस करने की अनुमति नहीं दी। याचिकाकर्ता 20 दिसंबर, 1985 को एम. बी. शर्मा, जे. द्वारा पारित आदेश पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार हैः-

"20.12.1985

श्री एम. आई. खान, राज्य के लोक अभियोजक।जमानत आवेदन दोपहर 2 बजे आदेश के लिए निर्धारित किया गया था और लोक अभियोजक के पास जांच अधिकारी से केस डायरी प्राप्त करने का समय था।मैं अंतिम 15 मिनट से अदालत में हूं, लेकिन वकीलों और अन्य लोगों ने अदालत में प्रवेश को रोक दिया है।अगस्त पेशे के सदस्यों को इस बात पर विचार करना है कि यह कितना उचित है। याचिकाकर्ता का अधिवक्ता उस नाकाबंदी के कारण अदालत में नहीं आ सका।इसलिए मामले को नहीं उठाया जा सकता है।मेरे पास चैंबर में सेवानिवृत्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।मामला 2 जनवरी, 1986 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

एस. डी./- शर्मा, एम. बी.

6. इसके बाद, उच्च न्यायालय को 21 दिसंबर, 1985 को शीतकालीन अवकाश के लिए बंद कर दिया गया। 20 दिसंबर, 1985 को याचिकाकर्ता को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस (सी. बी. आई., जयपुर) द्वारा हिरासत में ले लिया गया।उन्हें 22 दिसंबर, 1985 को 20 दिसंबर, 1985 से निलंबित कर दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन को 2 जनवरी, 1986 को निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया गया था। अस्थिर वातावरण को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की कि उसके खिलाफ सत्र न्यायाधीश, जयपुर के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 3/86 में निष्पक्ष

सुनवाई नहीं होगी। इसलिए, उन्होंने आपराधिक मुकदमे को स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।4 अगस्त, 1986 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उपरोक्त आपराधिक मामले में मुकदमे को दिल्ली में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।इसके बाद दिल्ली में मुकदमा विधिवत रूप से चलाया गया। 1 मई, 2002 के फैसले और आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा बरी कर दिया गया था।

7. निचली अदालत द्वारा दोषमुक्ति जाने पर, याचिकाकर्ता ने 6 मई, 2002 को राजस्थान उच्च निचली अदालत के महापंजीयक को एक संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अनुरोध उक्त तिथि से उच्च न्यायालय के विचाराधीन रहा। याचिकाकर्ता के दोषमुक्ति के खिलाफ अपील, यदि कोई हो, के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए निर्णय को स्थगित कर दिया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि सी. बी. आई. द्वारा एक अपील दायर की गई थी, जिसे 27 सितंबर, 2005 को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

8. याचिकाकर्ता ने 3 अक्टूबर, 2005 को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन उच्च न्यायालय ने कोई कार्रवाई नहीं की।17 नवंबर, 2005 को ही उन्हें जिला और सत्र न्यायाधीश, जयपुर के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। इस समय तक याचिकाकर्ता 20 साल की अवधि के लिए निलंबित था। इसलिए, उन्होंने 2 मार्च, 2006 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें शिकायतों को प्रस्तुत किया गया और मुख्य न्यायाधीश के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति मांगी गई।

9. इस बीच, याचिकाकर्ता को पता चला कि निलंबन के आदेश को रद्द करने के बजाय, उच्च न्यायालय उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है।उस

समय, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु से केवल 2 वर्ष कम था।इसलिए, उन्होंने निलंबन और परिणामी लाभों के आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की।8 मई, 2006 को इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि रिट याचिका दायर करने के बाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन निलंबन का कोई नया आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को तुरंत बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश जारी किया जाए।इस न्यायालय ने रिट याचिका और एकतरफा रोक के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया।इसके बाद, मामला 25 जनवरी, 2007 को सुनवाई के लिए आया जब इस अदालत ने निर्देश दिया कि मामले को मार्च, 2007 के अंतिम सप्ताह में अंतिम निपटान के लिए रखा जाए।4 जनवरी, 2008 को प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की कार्यवाही प्रगति पर है। इसलिए, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

10. जाँच विधिवत पूरी की गई। 27 फरवरी, 2008 की जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। 26 मार्च, 2008 के आदेश द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेशों को कुलसचिव (रिट) द्वारा दायर 22 अप्रैल, 2008 के शपथ पत्र के साथ इन कार्यवाही के रिकॉर्ड पर रखा गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता को 12 मई, 2008 को विजय नगर में नियुक्ति आदेश दिया गया। वे 30 जून, 2008 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के मुकदमे और क्लेश सेवानिवृत्ति के बाद भी समाप्त नहीं हुए।वास्तव में 24 जनवरी, 2009 को पूर्ण न्यायालय द्वारा 29 नवंबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर एक आदेश

जारी किया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार हल किया गया थाः-

"राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर। (आर. जे. एस.) 15/2009 तिथिः-24.01.2009

वर्तमान में सेवानिवृत्त आर. जे. एस. श्री गुरपाल सिंह को इस कार्यालय के आदेश सं. ऐसा है। (RJS) 199/85 dated22.12.1985। और जब यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत श्री गुरपाल सिंह के खिलाफ नियमित अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाए, तो आर. जे. एस. वर्तमान में सेवानिवृत्त है। और जहां माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 30 अक्टूबर, 1971 के पूर्ण न्यायालय प्रस्ताव के साथ पठित राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत नियमित जांच शुरू करने के कारण श्री गुरपाल सिंह का निलंबन जारी रहेगा। और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच उक्त श्री गुरपाल सिंह के खिलाफ ज्ञापन सं. ऐसा है।B2 (iii)// 2006/1544 dated20.04.2006। और उपरोक्त विभागीय जांच में कहा गया है कि श्री गुरपाल सिंह को आदेश सं. ऐसा है। (RJS) 25/2008 दिनांकित 26.03.2008।और जबकि, श्री गुरपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से सिविल जज (जूनियर) के रूप में बहाल कर दिया गया है।) और आर. जे. एस. में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश सं. ऐसा है।(RJS) 26/2008 दिनांकित 26.03.2008।

और जहाँ श्री गुरपाल सिंह के निलंबन की अवधि को नियमित करने के मामले पर माननीय पूर्ण न्यायालय द्वारा 29.11.2008 पर आयोजित अपनी बैठक में विचार

किया गया था और इसे निम्नानुसार हल किया गया थाः-

"प्रयुक्त कार्यालय ध्यान दें और प्रासंगिक रिकॉर्ड।हल किया गया कि उसके निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा, लेकिन उसे पहले से ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्तों को छोड़कर वेतन के बिना।हालाँकि, इससे उनके पेंशन लाभ प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन वे किसी भी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे।"

अब उसके निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा, लेकिन उसे पहले से ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्तों को छोड़कर वेतन के बिना। हालाँकि, इससे उनके पेंशन लाभ प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन वे किसी भी पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे।

आदेश द्वारा/24.01.2009REGISTRAR (ADMN.) "

12. इसलिए याचिकाकर्ता ने 2009 की आई. ए. संख्या 6 द्वारा से रिट याचिका में संशोधन की मांग की।संशोधन के लिए उपरोक्त आवेदन को इस न्यायालय द्वारा 27 फरवरी, 2009 को मंजूरी दी गई थी।संशोधन के बाद, प्रतिवादी द्वारा संशोधित रिट याचिका पर जवाबी शपथ पत्र दायर किया गया था।इस मामले की सुनवाई इस अदालत ने कई मौकों पर की थी।5 अप्रैल, 2011 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः-

"मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायाधीशालय की राय है कि यदि उच्च न्यायाधीशालय को नियमों के नियम 54 के तहत उचित आदेश देने का अवसर दिया जाता है तो न्यायाधीश के हित को पूरा किया जाएगा।इसलिए, मामला नियम 54 के तहत उचित आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय को उसके प्रशासनिक पक्ष पर भेजा जाता है।उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करना

करेगा और उसे नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए बुलाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद उच्च न्यायालय जवाब पर विचार करेगा और 1951 के नियमों के नियम 54 के तहत एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।यह कवायद जितनी जल्दी हो सके और बिना किसी टालने योग्य देरी के पूरी की जाएगी, लेकिन किसी भी मामले में आज से छह सप्ताह के बाद नहीं।उच्च न्यायालय आदेश दायर करेगा जो उसके द्वारा वर्तमान कार्यवाही में पारित किया जा सकता है।"

13. उपरोक्त निर्देश के अनुसरण में, यह प्रतीत होता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय (इसके बाद 'समिति' के रूप में संदर्भित) द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1951 (इसके बाद '1951 नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 54 के संदर्भ में याचिकाकर्ता के मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि "क्या उनका निलंबन पूरी तरह से उचित था या पूरी तरह से अन्यायपूर्ण या आंशिक रूप से उचित था और निलंबन की अवधि के दौरान वे किस हद तक वेतन और/या पूर्ण वेतन के हकदार थे?"

14. इस संबंध में, पंजीयक (प्रशासन) द्वारा याचिकाकर्ता को 25 अप्रैल, 2011 को एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें जवाब दाखिल करने और 5 मई, 2011 को उपरोक्त समिति के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था।उक्त नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता ने 2 मई, 2011 को एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया और 5 मई, 2011 को समिति के समक्ष पेश हुआ।इसके बाद 16 मई, 2011 को समिति ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

"इसलिए, वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों (सुप्रा) में, जिस अवधि के दौरान श्री गुरपाल सिंह निलंबन के तहत रहे, उसे पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है

और नकारात्मक रूप में आर. एस. आर. की धारा 54 का उप-नियम (2) जहां प्राधिकरण को यह जांचना है कि क्या निलंबन पूरी तरह से अनुचित था।हालाँकि, अभिलेख पर पूर्ण सामग्री (ऊपर) को देखने के बाद, न्यायालय का विचार है कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों (ऊपर) में, श्री गुरपाल सिंह के निलंबन को पूरी तरह द्वारा अनुचित नहीं कहा जा सकता है और कानून के तहत उन्हें जिसके लिए हकदार बनाया गया था, उद्वारा पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव की अवधि में उन्हें भुगतान कर दिया गया है। 2008 (ऊपर) आदेश डी. टी. के माध्यम से प्रेषित किया गया। 24.01.2009."

15. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, 24 जनवरी, 2009 के आदेश के माध्यम से सूचित 29 नवंबर, 2008 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव को दोहराया।

16. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

17. विद्वान सलाहकार द्वारा पक्षों के लिए बहुत विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई हैं। हालाँकि, हम प्रस्तुतियों के प्रत्येक सार पर संक्षेप में ध्यान दे सकते हैं।

18. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. आर. काला ने कहा कि प्रतिवादी को जिस दिन निलंबन आदेश पारित किया गया था, उस दिन यानी 20 दिसंबर, 1985 को इसे उचित ठहराना होगा।इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता का निलंबन 22 साल, 3 महीने और 7 दिनों तक जारी रहा था, इसलिए प्रतिवादी को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि इस तरह का लंबा निलंबन भी उचित था।निलंबन का आदेश न्यायोचित था या नहीं, आंशिक रूप से न्यायोचित था या पूरी तरह से अनुचित था, यह न केवल आपराधिक मामले में मुकदमे के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि विभागीय जांच के परिणाम के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जहां

याचिकाकर्ता को विभाग द्वारा आगे बढ़ाया गया था।विद्वान वरिष्ठ सलाहकार के अनुसार, 1951 के नियमों के नियम 54 के तहत निर्णय लेते समय, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आपराधिक मुकदमे और विभागीय कार्यवाही के परिणाम को ध्यान में रखना आवश्यक था।

19. इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा करते हुए, श्री काला ने प्रस्तुत किया था कि एक कर्मचारी जिसे आपराधिक जांच/मुकदमे के खर्च के कारण निलंबित किया गया है, उसे दोषमुक्ति पर बहाल किया जाना चाहिए। बहाली के बाद, वह निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, निचली निचली अदालत या अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति का फैसला उस तारीख से संबंधित होगा जिस दिन निलंबन का आदेश पारित किया गया था।श्री काला ने तब प्रस्तुत किया कि इस मामले के तथ्यों में, याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण निलंबित कर दिया गया था। उस समय जब याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था, वह बहाल होने का हकदार था।हालाँकि, चूंकि सी. बी. आई. द्वारा दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील दायर की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता को न तो बहाल किया गया और न ही उनका निलंबन रद्द किया गया।यहां तक कि जब उपरोक्त अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, तब भी याचिकाकर्ता के बहाली के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया था।श्री काला के अनुसार, यह दूसरा चरण था जब अपीलकर्ता बहाली और पूर्ण वेतन और भत्तों के भुगतान का हकदार था।श्री काला ने आगे बताया कि अधिग्रहण के बाद भी, अपीलकर्ता को अन्यायपूर्ण तरीके से विभागीय जांच के अधीन किया गया था।विभागीय जांच में आरोप उन तथ्यों पर आधारित थे, जिन पर हत्या का मकसद होने का आरोप लगाया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता को आपराधिक मुकदमे में बरी कर दिया गया था, इसलिए उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही पूरी तरह से अनुचित थी। इसलिए, श्री काला के

अनुसार, निलंबन को जारी रखना भी पूरी तरह से अनुचित था।

20. इस स्तर पर भी, प्रतिवादी ने 1951 के नियमों के नियम 54 के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया।5 अप्रैल, 2011 को इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर ही प्रतिवादी ने नियम 54 के तहत मामले की जांच की और 16 मई, 2011 को आवश्यक आदेश पारित किया।यह भी प्रस्तुत किया गया कि 16 मई, 2011 को इस न्यायालय के निर्देशों पर पारित आदेश 24 जनवरी, 2009 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विपरीत है। याचिकाकर्ता के निलंबन की अवधि को नियमित करने के संबंध में 26 मई, 2008 को याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने के बाद बाद का आदेश पारित किया गया था। नियम 54 के तहत पारित आदेश में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि जिस अवधि के दौरान अपीलकर्ता को निलंबित रखा गया था, उसे कर्तव्य पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा, लेकिन उसे पहले से ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते को छोड़कर वेतन के बिना।यहां तक कि यह आदेश वर्तमान याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान भी पारित किया गया था।श्री काला ने तब प्रस्तुत किया कि न केवल याचिकाकर्ता को निलंबन की अवधि के दौरान पूर्ण वेतन और भत्तों से वंचित कर दिया गया है, बल्कि पदोन्नति के लिए उनके मामले पर भी उस तारीख से प्रभावी रूप से विचार नहीं किया गया था जब उनके कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति और पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। श्री काला ने अपनी प्रस्तुति के समर्थन में कई निर्णयों पर भरोसा किया था जो इस प्रकार हैंः

श्री मन्नी लाल बनाम श्री परमई लाल और अन्य, मुहम्मद अयूब खुहरो बनाम सम्राट 2, रॉबर्ट स्टुअर्ट वाउचोप बनाम सम्राट 3, विद्या चरण शुक्ला बनाम पुरुषोत्तम लाल कौशिक 4, ओ. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ & Ors.5, आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ और Anr.6, पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली बनाम नरेंद्र सिंह, 7 नगर निगम, सिविल लाइंस, नागपुर और अन्र। बनाम रामचंद्र और Ors.8, जसबिर सिंहवी। पंजाब

एंड सिंध बैंक और अन्य.9, संभागीय अधीक्षक, उत्तर रेलवे और अन्र। बनाम आर. बी. हनीफी गोविंद प्रसाद बनाम भारत संघ, 11 भारत संघ और अन्य। बनाम के. वी. जानकीरमन और अन्य, भारत संघ और अन्य। बनाम संग्राम केशरी नायक, सुलेख चंद और सालेक चंद बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य, केरल राज्य और अन्य। बनाम ई. के. भास्करनपिल्लई, भारत संघ और अन्य। बनाम लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह काद्यान और अन्र।

21. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पल्लव शिशोदिया ने अन्य बातों के साथ-साथ देरी के आधार पर वर्तमान रिट याचिका को खारिज करने की मांग की। यह बताया गया कि 20 दिसंबर, 1985 के निलंबन के आदेश को चुनौती देने में 20 साल से अधिक की देरी हुई है।श्री काला की दलीलों के जवाब में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का प्रारंभिक निलंबन और उसे आगे जारी रखना, आपराधिक मुकदमे के दौरान; बरी होने के खिलाफ अपील विचाराधीनता रहने के दौरान; और विभागीय जांच विचाराधीनता रहने के दौरान; उनके द्वारा किए जा रहे "न्यायिक कार्य की संवेदनशील प्रकृति" को देखते हुए "न केवल उचित, बल्कि अनिवार्य" था।यह भी प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि आपराधिक मुकदमे या अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम का अनुमान लगाना कभी भी संभव नहीं है, जो संभवतः मामले में बरी या दोषमुक्ति हो सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता के निलंबन को "पूरी तरह से अनुचित" नहीं कहा जा सकता है।इसके अलावा, श्री शीशोदिया ने बताया कि याचिकाकर्ता को निचली निचली अदालत ने "संदेह के लाभ" पर बरी कर दिया था। इसके अलावा, अधिग्रहण के खिलाफ अपील को खारिज करने से किसी भी तरह से कानूनी स्थिति प्रभावित नहीं होती है।

22. श्री शीशोदिया द्वारा यह भी बताया गया था कि निलंबन के "दुर्भावनापूर्ण, प्रतिशोधी या अन्यथा प्रेरित" होने का कोई आरोप नहीं है, 24 जनवरी, 2009 के

विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जैसा कि 16 मई, 2011 के आदेश द्वारा पुष्टि की गई है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया था कि वर्तमान रिट याचिका में 16 मई, 2011 के आदेश को कोई चुनौती नहीं है, न ही याचिकाकर्ता ने यह प्रस्तुत किया था कि सी. बी. आई. द्वारा उनका अभियोजन दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा दूषित था।उपरोक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, यह तर्क दिया गया कि आपराधिक कार्यवाही और/या विभागीय जांच लंबित निलंबन पूरी तरह से उचित था।श्री शीशोदिया ने यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को पूर्ण वेतन से इनकार करने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों का ईमानदारी से प्रयोग करते हुए और 1951 के नियमों के नियम 54 की अच्छी तरह से स्थापित व्याख्या के आधार पर पारित किया गया था।

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा करते हुए आगे तर्क दिया था कि किसी कर्मचारी को उसके निलंबन की अवधि के दौरान वेतन, पदोन्नति और अन्य लाभों के अनुदान से संबंधित मामले नियोक्ता के विवेक के अधीन हैं।नियोक्ता को कर्मचारी के अधिकारों और संस्था की अनिवार्यताओं के बीच संतुलन बनाना होता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और उचित तरीके से कार्य करते हुए सीमा रेखा खींची है ताकि किसी भी असमान दंड से बचा जा सके।इसने याचिकाकर्ता की पात्रता और न्यायाधीश के प्रशासन के सार्वजनिक कर्तव्य के लिए जिम्मेदार संस्था की अनिवार्यताओं के बीच संतुलन स्थापित किया है।

24. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा था कि याचिकाकर्ता को जो भी राशि कानूनी रूप से देय थी, वह उसे पहले ही भुगतान कर दी गई है।यह कहा गया था कि केवल बारह लाख सत्तर तीन हजार आठ सौ बयालीस रुपये, अर्थात रु। 12,73,842-, याचिकाकर्ता को विभिन्न शीर्षों के तहत भुगतान किया गया है, जैसे कि महँगाई भत्ता, निर्वाह भत्ता, आदि। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को केवल बाईस हजार तीन सौ अड़तीस

रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, यानी रु। 22, 385/-।

वकील ने भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंधन, नई दिल्ली बनाम भोपाल सिंह पांचाल, कृष्णकांत रघुनाथ बिभवनेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, के. पोन्नम्मा (श्रीमती) की अपनी दलीलों को साबित करने के लिए निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया। बनाम केरल राज्य और अन्य, धनंजय बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलना, भारत संघ और अन्य। बनाम जयपाल सिंह, बलदेव सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, एन. सेल्वराज बनाम कुंभकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड और अन्य, बंशी धर बनाम राजस्थान राज्य और अन्र, मंडल नियंत्रक, गुजरात एस. आर. टी. सी बनाम कादरभाई J.Suthar, भारत संघ बनाम बी. एम. झा।

25. हमने पक्षों विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है।

26. इस स्तर पर एकमात्र मुद्दा जिसे हल करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता आपराधिक मामले में दोषमुक्ति और विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त होने के मद्देनजर केवल उसे पहले से दिए गए निर्वाह भत्ते या पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार होगा।उपरोक्त मुद्दे से संबंधित राजस्थान न्यायिक सेवा में उनके कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से काल्पनिक पदोन्नति का एक परिणामी मुद्दा होगा और पदोन्नति के पद पर परिलब्धियों की परिणामी पात्रता होगी, जो बदले में निलंबन भत्ते और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की राशि निर्धारित करेगी।

27. हमारी राय में, उद्धृत प्रत्येक निर्णय में अनुपात पर ध्यान देना वास्तव में आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे सभी कानून के कुछ प्रसिद्ध सिद्धांतों को दोहराते हैं।हालाँकि, हम विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में उजागर किए गए कुछ सिद्धांतों पर ध्यान दे सकते हैं।नागपुर नगर निगम (उपर्युक्त) के मामले में, यह देखा गया है कि उन्हीं

आरोपों या आधारों या साक्ष्य पर विभागीय जांच जारी रखना समीचीन नहीं हो सकता है, जहां अभियुक्त को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया है और आरोप से पूरी तरह से बरी कर दिया गया है।साथ ही, यह भी बताया गया है कि केवल इसलिए कि आरोपी को बरी कर दिया गया है, विभागीय जांच जारी रखने की संबंधित प्राधिकारी की शक्ति को नहीं खोया जाता है और न ही किसी भी तरह से उसके विवेक को बाधित किया जाता है।

28. यही सिद्धांत पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली बनाम नरेंद्र सिंह (ऊपर) के मामले में दोहराया गया है।

29. जसबिर सिंह के मामले (ऊपर) में, अपीलकर्ता प्रत्यर्थी बैंक में एक पुष्ट चपरासी था। इस आरोप पर कि उसने एक जमाकर्ता आर के जाली हस्ताक्षर किए थे और धोखाधड़ी से एक निश्चित राशि निकाल ली थी, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। भा.दं.सं. सी. की धारा 409/201 के तहत एक आपराधिक मामला भी शुरू किया गया था। उन्हें आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था।हालांकि, इस्तीफे के बावजूद, विभागीय कार्यवाही जारी रही और अंततः इस आशय की एक एकपक्षीय रिपोर्ट में समाप्त हो गई कि आरोप साबित हो गए थे।प्रत्यर्थी बैंक ने उक्त राशि की वसूली के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया।मुकदमे का फैसला सुनाया गया था लेकिन अपील न्यायालय ने माना कि बैंक यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने उक्त राशि को वापस ले लिया था या उसका गबन किया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि बैंक उक्त राशि की वसूली का हकदार नहीं था।उस फैसले को चुनौती दी गई थी।इस प्रकार, उसी ने अंतिमता प्राप्त की।हालाँकि, अनुशासनात्मक कार्यवाही और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।दीवानी अदालत के फैसले पर ध्यान दें दिए बिना और द्विदलीय समझौते के प्रावधान पर

भरोसा किए बिना, उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामले में दोषमुक्ति के फैसले के बाद भी विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती थी। अपीलकर्ता कर्मचारी ने तब इस न्यायालय में एक अपील दायर की।अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्थी बैंक ने इस मुद्दे पर एक सक्षम दीवानी अदालत से निष्कर्ष आमंत्रित किए हैं कि क्या अपीलकर्ता ने कोई गबन किया था या नहीं।सभी कार्यवाहियों में अपीलकर्ता के खिलाफ धन का गबन प्रमुख आरोप था।प्रत्यर्थी बैंक किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी आरोप को साबित करने में विफल रहा।दीवानी मामले में निर्णय ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, जो प्रतिवादी बैंक पर बाध्यकारी था।यह भी कहा गया कि इस तरह के मामले में, उच्च न्यायालय को अभिलेख में लाई गई सामग्री के संदर्भ में विषय-वस्तु के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए था।यह ऐसा करने में विफल रहा और दीवानी अदालत के फैसले पर ध्यान दें नहीं दिया।यह अभिलेख पर सामग्री को देखने से इनकार नहीं कर सकता था।इसलिए विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

30. ओ. पी. गुप्ता के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत पर जोर दिया कि कोई भी आदेश जो प्रतिकूल नागरिक परिणाम पैदा करेगा, केवल प्राकृतिक न्याय के नियमों के पालन पर ही पारित किया जा सकता है।इसलिए, "निष्पक्ष सुनवाई" की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है।इस बात पर भी जोर दिया गया कि लंबे समय तक निरंतर निलंबन सरकारी कर्मचारी को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है।चूँकि निलंबन का आदेश सरकारी कर्मचारी को केवल "निर्वाह भत्ता" का अधिकार देता है, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम होते हैं, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि "जीवन" अभिव्यक्ति केवल जानवरों के अस्तित्व या जीवन द्वारा से निरंतर कठिन परिश्रम को नहीं दर्शाती है।ये सभी कानून के जाने-माने सिद्धांत हैं।हम केवल उसी का संदर्भ देते हैं, क्योंकि मामले

उद्धृत किए गए हैं।

31. इसी तरह श्री शिशोदिया द्वारा उद्धृत निर्णय इस सिद्धांत को दोहराते हैं कि "कोई कठोर और तेज़ नियम" निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि क्या बहाली पर कर्मचारी पूर्ण वेतन का हकदार है या कोई वेतन नहीं।सभी मामले इस सिद्धांत को दोहराते हैं कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच संबंधित प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। इसे अभिलेख पर विषय-वस्तु के आधार पर एक सूचित निर्णय लेना होता है।ये निर्णय यह भी दोहराते हैं कि किसी कर्मचारी को दोषमुक्ति से वह स्वतः ही बहाली या पूर्ण वेतन के भुगतान का हकदार नहीं होगा।आम तौर पर विभागीय जांच करने की शक्ति अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास निहित होती है, यहां तक कि आपराधिक मुकदमे के समापन पर भी जहां कर्मचारी को बरी कर दिया जाता है।

32. हमने उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पूरे मुद्दे की जांच की है। बहाली पर वेतन और अन्य भत्तों के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता से संबंधित मुद्दे को निर्धारित आदेशने के लिए, मामले की विभिन्न चरणों/समय पर जांच आदेशने की आवश्यकता है।पहला चरण उस समय शुरू हुआ जब याचिकाकर्ता को शुरू में 22 दिसंबर, 1985 को 20 दिसंबर, 1985 से निलंबित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता, हमारी राय में, प्रारंभिक चरण में अपने निलंबन के खिलाफ वैध रूप से विरोध नहीं कर सकता है, जब वह अड़तालीस घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रहा था, हालांकि दुर्भाग्य से उन परिस्थितियों के लिए जिनके लिए वह जिम्मेदार नहीं था।यह निलंबन स्वाभाविक रूप से तब भी जारी रहा जब वह हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे थे।

33. अगला चरण वह है जब उन्हें 1 मई, 2002 को निचली निचली अदालत ने बरी कर दिया था।याचिकाकर्ता को बरी करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली

द्वारा की गई टिप्पणियां इस प्रकार हैंः-

"285. हाथ में केस मस्टर को पास नहीं करता है।जिन परिस्थितियों को सुरक्षित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है, उनमें केवल यह शामिल होगा कि आरोपी और मृतक के बीच लंबे समय से दोस्ती थी, और अप्राकृतिक मृत्यु का संकेत देने वाली परिस्थितियों में मृत शरीर की खोज हुई थी। अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे इस सिद्धांत को साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी ने राजस्व बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने में मदद करने के वादे पर मृतक से एक लाख 20 हजार रुपये की राशि ली थी, या मृतक को उक्त नियुक्ति प्राप्त करने में विफलता का सामना करना पड़ा था।घटना के बाद आरोपी द्वारा पीडब्लू 1 को एक लाख रुपये वापस करने का अनुमान संदिग्ध है।एफ. आई. आर. दर्ज प्राथमिकीने में अत्यधिक देरी होती है, जिसे सभी और विभिन्न लोगों के दावों की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जाता है कि उन्हें शुरू से ही अभियुक्तों की संलिप्तता का संदेह था, अस्पष्ट बना हुआ है और यह मामले (ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 607) के लिए घातक साबित होने के लिए बाध्य है।

286. "अंतिम बार देखे गए" के बारे में साक्ष्य आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं और बल्कि एक मनगढ़ंत साक्ष्य के रूप में सामने आए हैं।जांच के दौरान सबूत तैयार करने के प्रयासों, उदाहरण के लिए आरोपी के कहने पर खून से सने कपड़ों की बरामदगी, घटनास्थल से बरामद सामग्री के अनधिकृत संचालन के साथ, जहां शव पाया गया था, ने यह धारणा दी है कि उससे छेड़छाड़ की गई होगी।इससे अभियोजन पक्ष के मामले में विश्वास कम होता है।जाँच में अभियुक्त के खिलाफ कुछ तत्वों के प्रभाव में पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के संकेत दिए गए।परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली शंकाओं का लाभ अभियुक्त के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि संदेह, चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, अंतिम विश्लेषण में सबूत की जगह नहीं ले सकता है।" इन टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि निचली निचली अदालत ने अभियोजन मामले की नींव पर ही विश्वास

नहीं किया। कथित मकसद बिना किसी आधार के पाया गया है।निचली निचली अदालत का फैसला स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रस्तुत साक्ष्य याचिकाकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक तक भी नहीं पहुंचता है।अभियोजन पक्ष का यह सिद्धांत कि याचिकाकर्ता ने मृतक से पैसे की मांग की थी या पैसे लिए थे, किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था। निचली निचली अदालत ने यह भी देखा कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई थी, जिसे सभी और विभिन्न दावों की पृष्ठभूमि के खिलाफ देखा जाना था, कि उन्हें शुरू से ही याचिकाकर्ता की संलिप्तता पर संदेह था।निचली निचली अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक थी।निचली निचली अदालत ने यह भी कहा कि "आखिरी बार देखे गए" के संबंध में सबूत मनगढ़ंत थे और इसलिए, आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते थे।यह भी देखा गया है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की गई थी।निचली अदालत को एक निश्चित धारणा के साथ छोड़ दिया गया था कि साक्ष्य के साथ "छेड़छाड़" की गई थी।न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि "जांच में पक्षपात और पूर्वाग्रह की झलक देखने को मिली, जिसमें कुछ तत्वों का प्रभाव कम था, जो अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण थे।"हमारी राय में ये टिप्पणियां वर्तमान मामले को उन मामलों के दायरे में लाएंगी जिन्हें अक्सर "कोई सबूत नहीं" के मामलों के रूप में वर्णित किया जाता है।केवल इसलिए कि न्यायालय ने अंततः इस शब्द का उपयोग किया कि अभियोजन पक्ष मामले को "उचित संदेह से परे" साबित करने में विफल रहा है, इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कद पूरी तरह से अविश्वसनीय होने के स्तर से नहीं बढ़ेगा।

34. जैसा कि ऊपर देखा गया है, श्री काला ने कहा है कि याचिकाकर्ता का निलंबन इस स्तर पर रद्द कर दिया जाना चाहिए था।इस प्रस्ताव को प्रतिग्रहण करना करना संभव नहीं होगा कि जैसे ही निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया,

राजस्थान उच्च निचली अदालत को निलंबन के आदेश को तुरंत रद्द करने की आवश्यकता थी।निस्संदेह, याचिकाकर्ता को एक गैर-संवेदनशील नियुक्ति दी जा सकती थी, जिसमें न्यायिक कार्य शामिल नहीं थे। लेकिन, उच्च न्यायालय के लिए उस स्तर पर निलंबन को रद्द करना अनिवार्य नहीं था। यह रिकॉर्ड की बात है कि अभियोजन एजेंसी ने याचिकाकर्ता को बरी करते हुए निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया।सी. बी. आई. द्वारा दायर अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और 27 सितंबर, 2005 को निर्णय होने तक लंबित रही।इसलिए, निचली निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अंतिम नहीं थे।वे उच्च न्यायालय द्वारा अपील में उलट दिए जाने के लिए उत्तरदायी थे।इस प्रकार, उक्त अवधि/चरण के दौरान, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के निलंबन को जारी रखना पूरी तरह से अनुचित था।केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय निलंबन को निरस्त कर सकता था, निलंबन जारी रखने के निर्णय को पूरी तरह से अनुचित नहीं बनाता।

35. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के दोषमुक्ति जाने के फैसले को दोहराये जाने तक राजस्थान उच्च न्यायालय को बहुत ही जटिल स्थिति में रखा गया था।वस्तुतः, उच्च न्यायालय के पास याचिकाकर्ता को निलंबित करने और रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।ऐसा नहीं था कि याचिकाकर्ता ने अनजाने में एक यातायात विनियमन का उल्लंघन किया था, जो आम जनता से एक नाराज़गी भी आमंत्रित नहीं कर सकता है। यह भी नहीं था कि उनका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मामूली झगड़ा हो सकता है जिसे एक समझदार व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई नैतिक पतन शामिल नहीं होगा। वह हत्या के अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहा था, जो उच्चतम नैतिक अधमता का अपराध था।अनादिकाल से, न्यायाधीशों को हर सभ्य समाज में बहुत ऊँचे स्थान पर

रखा गया है।इस तरह की उच्च स्थिति के साथ एक न्यायाधीश की गरिमा, शिष्टता और सत्यनिष्ठा के असामान्य रूप से उच्च मानक को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। इसके बारे में कोई दो तरीके नहीं हो सकते हैं! इसलिए, याचिकाकर्ता के निलंबन को जारी रखने के उच्च न्यायालय के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसके इस्तीफे तक पूरी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

36. इस स्तर पर, हम केवल एक न्यायाधीश से अपेक्षित व्यवहार के उच्च मानकों के संबंध में इस न्यायालय के दो निर्णयों में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दया शंकर अन्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अन्य में। पंजीयक द्वारा से, इस अदालत ने निम्नानुसार टिप्पणी की"ः न्यायिक अधिकारी के दो मानक नहीं हो सकते हैं, एक न्यायालय में और दूसरा न्यायालय के बाहर उनके पास ईमानदारी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का केवल एक ही मानक होना चाहिए। वे अपने पद के अयोग्य भी नहीं हो सकते हैं।"इसके अलावा, सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम के मामले में। भट्टाचार्जी और अन्य, 28 फिर से एक न्यायिक अधिकारी द्वारा धारण किए गए पद की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन कियाः

"21. न्यायिक कार्यालय अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक न्यास है।इसलिए, समाज को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि एक न्यायाधीश उच्च सत्यनिष्ठा, ईमानदारी वाला व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास नैतिक शक्ति, नैतिक दृढ़ता और भ्रष्ट या नकारात्मक प्रभावों के लिए अपरिहार्य होना चाहिए। उसे न्यायिक आचरण में उपयुक्तता के सबसे सटीक मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई भी आचरण जो न्यायालय की अखंडता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कम करता है, न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए हानिकारक होगा। इसलिए समाज यह अपेक्षा करता है कि जज से आचरण और शुद्धता के उच्च मानक एक बुनियादी

आवश्यकता है कि एक न्यायाधीश का आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण अनुचितता से मुक्त हो; यही योग्यता और ईमानदारी के उच्चतम मानक के अनुरूप होना चाहिए। आचरण का मानक एक आम आदमी से अपेक्षा की तुलना में अधिक है और एक अधिवक्ता से अपेक्षा की तुलना में भी अधिक है।वास्तव में, उनके निजी जीवन को भी ईमानदारी और औचित्य के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए, जो दूसरों के लिए स्वीकार्य मानकों से अधिक हैं।इसलिए, न्यायाधीश समाज में गिरते स्तर से शरण लेने का जोखिम नहीं उठा सकता है।"

37. याचिकाकर्ता के निलंबन को कम रखने के उच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय उपरोक्त 28 (1995) 5 एस. सी. सी. 457 मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।इसलिए, हम श्री काला के इस कथन को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं कि निचली निचली अदालत द्वारा आपराधिक आरोपों से बरी किए जाने के बाद याचिकाकर्ता का निलंबन पूरी तरह से अनुचित था।38.अब हम उच्च न्यायालय द्वारा अधिग्रहण के खिलाफ अपील खारिज किए जाने के बाद मंच पर आते हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की और अपने फैसले द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि अभियोजन कथित हत्या के लिए किसी भी उद्देश्य को साबित करने में विफल रहा था। उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया है कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह आगे देखा गया है कि मृतक को लगी चोटें इस दलील के साथ असंगत नहीं थीं कि यह आकस्मिक मृत्यु का मामला था। उच्च न्यायालय ने मृतक को याचिकाकर्ता के साथ "आखिरी बार" जीवित देखे जाने के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों पर भी अविश्वास किया।उद्देश्य के संबंध में साक्ष्य पर विश्वास न करने और याचिकाकर्ता के साथ पीड़ित को "आखिरी बार" जीवित देखे जाने के संबंध में, उच्च न्यायालय ने धारा 27 के तहत प्रकटीकरण

बयान और साक्ष्य के आपत्तिजनक टुकड़ों की बरामदगी के संबंध में साक्ष्य की जांच करने के लिए आगे बढ़े।प्रत्येक मुद्दे की जांच करने पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्य "गुप्त सूचनाओं की कहानी की वास्तविकता पर संदेह का निशान लगाते हैं"। उच्च न्यायालय ने कथित रूप से मृतक के कपड़ों की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया।खून के दाग की बरामदगी की कहानी पर भी विश्वास नहीं किया गया था।अंततः, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किएः-

"43. वर्तमान मामले में, कथित अपराध और अभियुक्तों के बीच प्रमुख संबंध पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं हैं। उपरोक्त विमर्श सकारात्मक रूप से दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए हर कदम पर विफल रहा है। पहला कदम यह साबित करना था कि यह दुर्घटना के बजाय हत्या का मामला था। अभियोजन पक्ष उचित संदेह के बिना यह साबित करने में विफल रहा है कि यह हत्या का मामला था न कि दुर्घटना का।

44. दूसरा कदम यह साबित करना था कि आरोपी और मृतक को आखिरी बार घटना से पहले एक साथ देखा गया था।अभियोजन पक्ष भी इस तथ्य को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।इस मामले में ऊपर जो महत्वपूर्ण तथ्य पहले ही कहा जा चुका है, उसके अलावा सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट के साथ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृतक के पेट में शराब की मौजूदगी है।यह दुर्घटना सिद्धांत का समर्थन करता है।

45. तीसरा कदम यह साबित करना था कि अभियोजन पक्ष ने या तो प्रकटीकरण बयान के बाद या अपनी पहल पर आपत्तिजनक लेख बरामद किए थे। अभियोजन पक्ष ऐसा करने में भी विफल रहा है। इस स्थिति में, भले ही अभियोजन पक्ष उद्देश्य के अस्तित्व को साबित करने में समर्थ हो, लेकिन स्वयं इसका कोई मूल्य नहीं होगा।निचली निचली अदालत ने मकसद की कहानी पर विश्वास नहीं किया है।

हालाँकि, हमारे लिए उन विवरणों में जाना आवश्यक नहीं है।

46. .....अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि पहली बात यह है कि कोई हत्या हुई थी और दूसरी बात यह है कि आरोपी वही है जिसने इसे किया था।अपील में पूरी तरह से कोई योग्यता नहीं है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है"

39. दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के दोषमुक्ति की पुष्टि किए जाने के बाद, हमारी राय में, राजस्थान के उच्च न्यायालय के लिए निर्णय लेना आवश्यक थाः(क) क्या निलंबन के आदेश को निरस्त किया जाए और याचिकाकर्ता को न्यायिक कार्य करने की अनुमति दी जाए; (ख) क्या उसे मृतक से प्राप्त धन की प्राप्ति के संबंध में विभागीय जांच की जाए; (ग) निलंबन की अवधि को कैसे माना जाए; (घ) क्या याचिकाकर्ता निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन, आंशिक वेतन या बिना वेतन का हकदार था।

40. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए, जिसे बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया था, याचिकाकर्ता के निलंबन को जारी रखने का निर्णय, उसके बाद, काफी कठोर था। यह सच है कि याचिकाकर्ता का निलंबन जारी रहा क्योंकि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ इस आरोप पर विभागीय जांच करने का फैसला किया था कि उसने मृतक से गलत तरीके से धन निकाला था। लेकिन यह रिकॉर्ड की बात है कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत दोनों ने कथित रूप से धन की प्राप्ति के संबंध में पूरी कहानी को गलत पाया। जाँच उन्हीं तथ्यों और उन्हीं साक्ष्यों पर आधारित थी जिनकी जाँच निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत द्वारा भी की गई थी।ऐसी परिस्थितियों में, उच्च निचली अदालत के लिए यह आवश्यक था कि वह याचिकाकर्ता

के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेने से पहले निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत के निष्कर्षों की विस्तार से जांच करे, जो तथ्यों और साक्ष्यों के एक ही समूह पर आधारित हो।रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय द्वारा फैसले की ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी।याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लेने के बाद भी, याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत जारी रखना अनिवार्य नहीं था। याचिकाकर्ता पर अब किसी भी आपराधिक अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था क्योंकि निचली अदालत और साथ ही उच्च निचली अदालत दोनों ने शाब्दिक रूप से निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप मनगढ़ंत थे। याचिकाकर्ता को 22 दिसंबर, 1985 से निरंतर निलंबन का सामना करना पड़ा था। विभागीय कार्यवाही की अवधि के दौरान, भले ही याचिकाकर्ता को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, उच्च न्यायालय आसानी से उसे प्रशासनिक पक्ष में उपयुक्त नियुक्ति दे सकता था।हमारी राय में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपील को खारिज करने के समय से, याचिकाकर्ता का निरंतर निलंबन पूरी तरह से अनुचित था।

41. एक बार फिर यह रिकॉर्ड की बात है कि विभागीय जांच में भी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए और उसे बरी कर दिया गया।यह केवल उस स्तर पर था जब याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द कर दिया गया था।दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के आदेश को बरकरार रखे जाने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता पहले ही वर्तमान रिट याचिका दायर कर चुका था। रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान जांच की कार्यवाही पूरी हो गई थी। निस्संदेह, उच्च न्यायालय द्वारा 26 मार्च, 2008 को निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया गया था, लेकिन बिना कोई निर्देश दिए कि निलंबन की अवधि को कैसे माना जाना था।इसके बाद ही 29 नवंबर, 2008 को हुई बैठक में पूर्ण न्यायालय द्वारा उनके निलंबन की अवधि को नियमित करने के मामले

पर विचार किया गया।यहां तक कि उस स्तर पर भी पूर्ण न्यायालय ने एक प्रस्ताव पारित किया कि निलंबन की अवधि को कर्तव्य पर खर्च की गई अवधि के रूप में माना जाएगा, लेकिन यह उसे पहले से ही भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते को छोड़कर किसी भी वेतन के भुगतान के बिना होना था।उपरोक्त संकल्प के आधार पर, उच्च न्यायालय ने 24 जनवरी, 2009 का आदेश पारित किया।इसलिए 24 जनवरी, 2009 के आदेश द्वारा भी याचिकाकर्ता को केवल आंशिक राहत दी गई थी।इसने याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका में संशोधन की आवश्यकता पैदा कर दी।यह केवल उस स्तर पर था कि इस न्यायालय ने 5 अप्रैल, 2011 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय को नियमों के नियम 54 के तहत उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।ऐसा प्रतीत होता है कि उस स्तर पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कोई और राहत देना आवश्यक नहीं समझा।

42. ऊपर वर्णित घटनाओं के इन अनुक्रमों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता को उस तारीख से वेतन से इनकार करना अन्यायपूर्ण होगा, जिस तारीख को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी।हम इस बात का कोई ठोस कारण नहीं देखते हैं कि विभागीय कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान याचिकाकर्ता का निलंबन जारी रखना क्यों आवश्यक था।आपराधिक मुकदमे के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही में तथ्यों या सबूतों के बीच कोई अंतर नहीं था।इसके अलावा, याचिकाकर्ता को हत्या के अपराध में किसी भी तरह की संलिप्तता से बरी कर दिया गया था।नियम 54 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के लिए एक विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेश पारित करना आवश्यक था कि क्या निलंबन की अवधि पूरी तरह से अनुचित थी।निस्संदेह, नियम 54 के तहत शक्ति विवेकाधीन है लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार का उपयोग उचित रूप से और निर्णय के लिए प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए

किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता के आपराधिक आरोपों से दोषमुक्ति पर, विभागीय पूछताछ विचाराधीनता रहने के दौरान उसे निलंबित रखने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी राय में, उच्च न्यायालय नियम 54 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का ठीक से प्रयोग करने में विफल रहा, जैसा कि इस अदालत द्वारा 5 अप्रैल, 2011 के आदेश में निर्देशित किया गया था।हमारी राय में, विभागीय जांच के लंबित रहने के दौरान भी उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने पर याचिकाकर्ता के निलंबन को रद्द कर दिया जाना चाहिए था।

43. यह अब हमें श्री काला के अंतिम निवेदन की ओर ले जाता है कि विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त होने के बाद, याचिकाकर्ता को उस तारीख से पदोन्नति के लिए विचार करने की आवश्यकता थी जब उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत किया गया था।

44. जानकीरमन (उपरोक्त) के मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए आधिकारिक फैसले को देखते हुए, श्री कल्ला द्वारा की गई दलीलों को स्वीकार करना होगा।उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः-

"26. इसलिए, हम व्यापक रूप से न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि जब कोई कर्मचारी पूरी तरह से दोषमुक्त हो जाता है जिसका अर्थ है कि वह कम से कम दोषी नहीं पाया जाता है और उसे निंदा के दंड के साथ भी नहीं देखा जाता है, तो उसे उच्च डाक के वेतन का लाभ उस तारीख से अन्य लाभों के साथ दिया जाना चाहिए जिस दिन उसे सामान्य रूप से पदोन्नत किया जाता, लेकिन अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही के लिए।"

45. इस मामले में, यह रिकॉर्ड की बात है कि विभागीय जांच में दोषमुक्त होने पर, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया गया था।उसे कोई सजा नहीं दी गई। हालाँकि, आपराधिक मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान, अन्य विभागीय कार्यवाही के

रूप में, उन्हें पदोन्नति के लिए नहीं माना जाता था, जब उनके कनिष्ठ व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जाता था।हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने 29 नवंबर, 2008 के पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव और 24 जनवरी, 2009 के संचार में अप्रत्यक्ष रूप से गलती की कि याचिकाकर्ता किसी भी पदोन्नति का हकदार नहीं होगा।

46. इसलिए हम आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति देते हैं।हम श्री काला की इन दलीलों को खारिज करते हैं कि निचली निचली अदालत द्वारा दोषमुक्ति जाने पर याचिकाकर्ता के निलंबन को पूरी तरह से अनुचित बना दिया गया था।हम श्री कैलाथ की दलीलों को भी खारिज करते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीनता रहने के दौरान याचिकाकर्ता का निलंबन पूरी तरह से अनुचित था।हालाँकि, हमारा मानना है कि विभागीय कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान याचिकाकर्ता का निरंतर निलंबन पूरी तरह से अनुचित था।इसलिए, याचिकाकर्ता को 27 सितंबर, 2005 से पूर्ण वेतन और भत्तों का हकदार माना जाता है, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की तारीख।हम आगे यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता उस तारीख से पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार था जब उसके कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत किया गया था। इसलिए हम उच्च न्यायालय को उस तारीख से पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हैं (यदि वह नियमों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करता है) जब उससे कनिष्ठ व्यक्ति पर विचार किया गया था और अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था।इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाए।हम आगे निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति जाने के खिलाफ अपील खारिज किए जाने की तारीख से और अपना अंतिम वेतन सही ढंग से तय करने के बाद सभी परिणामी लाभों, ऐसे वेतन और अन्य भत्तों का हकदार होगा।27 सितंबर, 2005 को उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने की तारीख से उसे 6 प्रतिशत

ब्याज के साथ परिणामी लाभों का भुगतान किया जाएगा।इस आदेश की प्रति की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर उसे बढ़े हुए सेवानिवृत्ति लाभ जारी किए जाएंगे।

47. यह मानते हुए कि राजस्थान उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को दोषमुक्ति जाने की पुष्टि होने के बाद अपनी खुद की विभागीय जांच करना चाहता था, उस अवधि के दौरान उनका निलंबन पूरी तरह से अनावश्यक था, जिसके कारण उन्हें अनावश्यक रूप से नुकसान उठाना पड़ा और आगे मुकदमेबाजी करनी पड़ी।इसलिए, हम रुपये की लागत प्रदान करते हैं। 25, 000/- याचिकाकर्ता को प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा वहन किया जाएगा।

आर. पी. रिट याचिका आंशिक स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।